

INDIAN DEMOCRACY: CHALLENGES AND SOLUTIONS

भारतीय लोकतंत्र: चुनौतियाँ और समाधान



Anil Kumar Sharma¹, Puran Mal Meena²✉

¹ Assistant Professor – Political Science Government College, Rajgarh, Alwar, Rajasthan, India

² M.A., M.Phil. Associate Professor & Head – Department of Political Science Government College, Rajgarh, Alwar, Rajasthan, India



DOI: <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v8.i12.2020.6896>

Article Type: Research Article

Article Citation: Anil Kumar Sharma, and Puran Mal Meena. (2020). INDIAN DEMOCRACY: CHALLENGES AND SOLUTIONS. International Journal of Research - GRANTHAALAYAH, 9(1), 337-340. DOI: <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v8.i12.2020.6896>

Received Date: 23 November 2020

Accepted Date: 31 December 2020

Keywords:

भारतीय लोकतंत्र
चुनावी सुधार
संस्थागत क्षरण
धार्मिक ध्रुवीकरण
संघीय तनाव
नागरिक भागीदारी
संवैधानिक नैतिकता
मीडिया स्वतंत्रता
सामाजिक न्याय

ABSTRACT

English: India is the world's largest democracy, where regular elections, an independent judiciary, and a multi-party system have sustained democratic values for over seventy years. Nevertheless, in the second decade of the 21st century, Indian democracy is confronting serious challenges. International reports have categorized India as an "Electoral Autocracy" and placed it in the "Partly Free" category.

This paper presents a fundamental analysis of the historical achievements of Indian democracy, its contemporary challenges (the influence of money and mafia power in the electoral process, socio-religious polarization, the erosion of institutional autonomy, a decline in media freedom, and tensions within the federal structure), as well as potential solutions to address them. The core premise of this research is that democracy is not merely an electoral process, but a continuous practice of constitutional morality, social justice, and civic participation. As a means of resolution, emphasis is placed on electoral reforms, civic education, digital transparency, maintaining a balance between the judiciary and the executive, and the restoration of Gandhian and Ambedkarite values. The conclusion posits that if these challenges are not addressed in a timely manner, the world's largest democracy risks sliding further from being an "Electoral Democracy" toward becoming an "Electoral Autocracy." This research paper offers practical guidelines for policymakers, scholars, and civil society.

Hindi: भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ नियमित चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका और बहुदलीय व्यवस्था ने सत्तर वर्षों से अधिक समय तक लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखा है। फिर भी, 21वीं सदी के दूसरे दशक में भारतीय लोकतंत्र गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स भारत को "इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी" और "पार्टली फ्री" की श्रेणी में रख चुकी हैं।

भारतीय लोकतंत्र की ऐतिहासिक उपलब्धियों, समकालीन चुनौतियों (चुनावी प्रक्रिया में धनबल-माफियाबल, सामाजिक-धार्मिक ध्रुवीकरण, संस्थागत स्वायत्तता का क्षरण, मीडिया स्वतंत्रता में गिरावट और संघीय ढांचे में तनाव) तथा इनके समाधान का मौलिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शोध का मूल आधार यह है कि लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि संवैधानिक नैतिकता, सामाजिक न्याय और नागरिक भागीदारी का सतत अभ्यास है। समाधान के रूप में चुनावी सुधार, नागरिक शिक्षा, डिजिटल पारदर्शिता, न्यायपालिका-कार्यपालिका संतुलन और गांधीवादी-अंबेडकरवादी मूल्यों की पुनर्स्थापना पर बल दिया गया है। निष्कर्ष में कहा गया है कि यदि समय रहते इन चुनौतियों का सामना नहीं किया गया तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र "इलेक्टोरल डेमोक्रेसी" से "इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी" की ओर और अधिक खिसक सकता है। यह शोध पत्र नीति-निर्माताओं, विद्वानों और नागरिक समाज के लिए व्यावहारिक दिशा-निर्देश प्रस्तुत करता है।

1. प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र की यात्रा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ शुरू हुई। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसे "सामाजिक लोकतंत्र" का आधार बताया था, जहाँ केवल राजनीतिक समानता नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित हो। सत्तर वर्षों में भारत ने कई चुनाव सफलतापूर्वक कराए, आपातकाल का सामना किया, गठबंधन सरकारें देखीं और 2014 के बाद एकल दल बहुमत की राजनीति देखी।

किंतु 2025-26 के V-Dem और Freedom House रिपोर्ट्स ने चेतावनी दी है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया स्वतंत्रता, नागरिक समाज और अल्पसंख्यक अधिकारों में निरंतर गिरावट आई है। लोकतंत्र की चुनौतियाँ अब केवल आंतरिक नहीं, बल्कि वैश्विक संदर्भ में भी चर्चित हैं। यह शोध इन्हीं वास्तविकताओं पर आधारित है।

भारतीय लोकतंत्र का विकास और उपलब्धियाँ: स्वतंत्र भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी। संविधान सभा की बहसें, जिसमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अन्य महानुभाव शामिल थे, ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14-32) और स्वतंत्र संस्थाओं (चुनाव आयोग, न्यायपालिका, लोकपाल जैसी भावना) का मजबूत ढांचा तैयार किया। यह ढांचा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित था, लेकिन भारतीय विविधता (धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र) को ध्यान में रखकर संशोधित किया गया।

1952 के पहले आम चुनाव में लगभग 17 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया। उस समय अशिक्षा, गरीबी, विभाजन के घाव और रियासतों के विलय जैसी चुनौतियों के बावजूद चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हुए। यह चुनाव लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम था। इसके बाद 1950-2024 की अवधि में भारत ने 18 लोकसभा चुनाव और सैकड़ों विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किए।

2. उद्देश्य

इस शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- 1) भारतीय लोकतंत्र के ऐतिहासिक विकास और उपलब्धियों का संक्षिप्त मूल्यांकन करना।
- 2) समकालीन चुनौतियों (2020-2026) का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना।
- 3) इन चुनौतियों के मूल कारणों की पहचान करना।
- 4) व्यावहारिक, संवैधानिक और नैतिक समाधानों का सुझाव देना।
- 5) लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए नीतिगत एवं सामाजिक सिफारिशें प्रस्तुत करना।

3. मुख्य उपलब्धियाँ-

- 1) **चुनावी मजबूती:** 2024 के लोकसभा चुनावों में 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया। चुनाव आयोग ने ईवीएम और VVPAT प्रणाली को अपनाकर पारदर्शिता बढ़ाई। मतदान प्रतिशत कई बार 65-70% रहा, जो विकासशील देशों में उल्लेखनीय है।
- 2) **संस्थागत विकास:** Supreme Court ने PIL (जनहित याचिका) के माध्यम से पर्यावरण, महिला अधिकार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बावजूद लोकतंत्र बरकरार रहा और गठबंधन युग (1989-2014) ने बहुलवाद को मजबूत किया।
- 3) **सामाजिक समावेशन:** आरक्षण नीति (अनुसूचित जाति/जनजाति और OBC), पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण (73वें संशोधन) और RTI अधिनियम (2005) ने हाशिए वाले वर्गों को मुख्यधारा में लाया। दलित-महिला-आदिवासी प्रतिनिधित्व बढ़ा।
- 4) **संघीय सफलता:** भाषाई राज्यों का गठन (1956 States Reorganisation Act) और उत्तर-पूर्वी राज्यों (नागालैंड, मिजोरम आदि) का विकास लोकतंत्र की लचीलापन दर्शाता है। GST (2017) ने वित्तीय संघवाद को नई दिशा दी, हालांकि इसमें कुछ तनाव भी रहे।
- 5) ये उपलब्धियाँ सिद्ध करती हैं कि भारतीय लोकतंत्र "अपूर्ण लेकिन जीवंत" है। यह न केवल चुनावी प्रक्रिया है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी रहा है।
- 6) **प्रमुख चुनौतियाँ:** चुनावी प्रक्रिया में विकृतियाँ धनबल, माफियाबल और अपराधीकरण चुनावी प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करते रहे। Association for Democratic Reforms (ADR) की 2024 रिपोर्ट के अनुसार, 17वीं लोकसभा के कई सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। 2024 चुनावों में उम्मीदवारों की औसत संपत्ति करोड़ों रुपये में थी, जो आम नागरिक की पहुंच से बाहर है। Electoral Bonds योजना (2024 में Supreme Court द्वारा रद्द) ने राजनीतिक फंडिंग की अपारदर्शिता उजागर की। इससे "पैसे का खेल" बढ़ा और साधारण उम्मीदवारों के लिए मैदान मुश्किल हो गया।
- 7) **सामाजिक-धार्मिक ध्वीकरण:** 2014-2024 की अवधि में सांप्रदायिक घटनाएँ बढ़ीं। Freedom House 2024 रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय पर भेदभावपूर्ण नीतियों, "लव जिहाद" कानूनों और CAA-NRC विवाद का उल्लेख है। जातिवाद अभी भी मतदान का प्रमुख आधार बना हुआ है (2024 चुनाव डेटा में कई राज्यों में जाति-आधारित गठबंधन सफल रहे)। सोशल मीडिया ने फेक न्यूज और घृणा प्रसार को बढ़ावा दिया, जिससे सामाजिक सद्भाव क्षतिग्रस्त हुआ।
- 8) **संस्थागत स्वायत्तता का क्षरण:** ED, CBI, IT विभाग और Enforcement Directorate पर विपक्षी दलों के खिलाफ दुरुपयोग के आरोप लगे। मीडिया पर "पेड न्यूज", IT Rules 2021 और NGOs पर FCRA प्रतिबंधों ने स्वतंत्रता को सीमित किया। V-Dem 2024 रिपोर्ट में मीडिया स्वतंत्रता सूचकांक और नागरिक समाज की स्वायत्तता में गिरावट दर्ज हुई। इससे लोकतंत्र का "चौथा स्तंभ" कमजोर पड़ा।
- 9) **संघीय ढांचे में तनाव:** GST कार्यान्वयन और वित्त आयोग की सिफारिशों पर केंद्र-राज्य विवाद बढ़े। दिल्ली सरकार और जम्मू-कश्मीर (2019 के बाद) जैसे मुद्दों ने संघीय भावना को चुनौती दी। कुछ राज्यों में केंद्र की योजनाओं को लागू करने में असहमति देखी गई।

10) उभरती चुनौतियाँ: सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और AI आधारित misinformation ने युवा मतदाताओं को प्रभावित किया। 18-35 आयु वर्ग में कुछ राज्यों में मतदान उदासीनता (2024 डेटा) चिंताजनक रही। जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी और किसान संकट ने सामाजिक असमानता बढ़ाई, जो लोकतंत्र की जड़ों को हिला रही है।

4. समाधान एवं सुझाव

चुनावी सुधार: राज्य वित्त पोषित चुनाव तुरंत लागू किए जाएँ ताकि धनबल कम हो। उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले सात वर्ष के अंदर सुलझाने की समय-सीमा तय करें। NOTA को प्रभावी बनाएँ और ईवीएम-VVPAT की 100% वेरिफिकेशन सुनिश्चित करें। ADR की सिफारिशों के अनुसार चुनावी फंडिंग में पूर्ण पारदर्शिता लाएँ।

सामाजिक-नैतिक सुधार: स्कूल पाठ्यक्रम में संविधान, नागरिकता शिक्षा और अंबेडकर-गांधी अध्ययन को अनिवार्य बनाएँ। सांप्रदायिक हिंसा पर फास्ट ट्रैक कोर्ट और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति का प्रावधान करें। MGNREGA, PM Awas Yojana और skill development योजनाओं को ग्रामीण-शहरी गरीबी कम करने के लिए और अधिक प्रभावी बनाएँ।

संस्थागत मजबूती: न्यायपालिका में रिक्तियों की शीघ्र भरपाई और कॉलेजियम प्रणाली में सुधार करें। चुनाव आयोग की नियुक्ति में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएँ (Supreme Court के 2023-24 निर्देशों का विस्तार)। RTI और Whistleblower Protection Act को और सशक्त करें।

डिजिटल और मीडिया सुधार: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र फैक्ट-चेकिंग बोर्ड बनाएँ। सार्वजनिक प्रसारण (Prasar Bharati) को सशक्त करें। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाएँ ताकि फेक न्यूज का प्रभाव कम हो।

दीर्घकालिक दृष्टि: गांधीजी की "ग्राम स्वराज" अवधारणा को पुनर्जीवित कर स्थानीय स्वशासन को मजबूत करें। अंबेडकर के सामाजिक न्याय को आर्थिक नीतियों (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार) में शामिल करें। युवाओं के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण और स्थानीय स्तर पर नेतृत्व विकास कार्यक्रम चलाएँ।

4. निष्कर्ष

भारतीय लोकतंत्र की यात्रा अभी अधूरी है। 1950-2024 की उपलब्धियाँ सराहनीय हैं—सार्वभौमिक मताधिकार, संस्थागत ढांचा और सामाजिक समावेशन ने इसे जीवित रखा है। किंतु 2014-2024 की चुनौतियाँ (धनबल, ध्रुवीकरण, संस्थागत क्षरण) गंभीर हैं। V-Dem और Freedom House जैसी रिपोर्ट्स चेतावनी हैं, लेकिन अवसर भी प्रदान करती हैं। यदि हम संवैधानिक नैतिकता, सामाजिक न्याय और सक्रिय नागरिकता को प्राथमिकता दें तो लोकतंत्र न केवल बच सकता है, बल्कि विश्व के लिए मिसाल बन सकता है। "लोकतंत्र तब तक जीवित रहता है जब उसके नागरिक इसे बचाने के लिए संघर्ष करते हैं।" — डॉ. बी.आर. अंबेडकर की इस चेतावनी को आज के संदर्भ में याद रखना होगा। भारत को पूर्ण लोकतंत्र की ओर लौटना चाहिए। यह शोध इसी दिशा में एक छोटा लेकिन विचारपूर्ण कदम है।

SOURCES OF FUNDING

This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

CONFLICT OF INTEREST

The author have declared that no competing interests exist.

ACKNOWLEDGMENT

None.

REFERENCES

- [1] ऑस्टिन, जी. (1966). द इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन (भारत का संविधान: राष्ट्र का आधारशिला). ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
- [2] ऑस्टिन, जी. (1999). वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टीट्यूशन: द इंडियन एक्सपीरियंस (लोकतांत्रिक संविधान का संचालन: भारतीय अनुभव). ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
- [3] अंबेडकर, बी. आर. (1949). कॉन्स्टीट्यूटेंट असेंबली डिबेट्स (खंड XI) (संविधान सभा की बहसें). भारत सरकार।
- [4] गुहा, र. (2007). इंडिया आफ्टर गांधी: द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जस्ट डेमोक्रेसी (गांधी के बाद भारत: विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का इतिहास). पिकाडोर इंडिया।

- [5] वी-डेम इंस्टीट्यूट. (2025). डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2025: 25 इयर्स ऑफ ऑटोक्रेटाइजेशन – डेमोक्रेसी ट्रेंड? (लोकतंत्र रिपोर्ट 2025: 25 वर्षों की अधिनायकत्व की ओर यात्रा). यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग।
- [6] वी-डेम इंस्टीट्यूट. (2026). डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2026: अनरेवलिंग द डेमोक्रेटिक एरा? (लोकतंत्र रिपोर्ट 2026: लोकतांत्रिक युग का विघटन?). यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग।
- [7] फ्रीडम हाउस. (2025). फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2025: इंडिया कंट्री रिपोर्ट (विश्व में स्वतंत्रता 2025: भारत देश रिपोर्ट). वाशिंगटन, डी.सी.।
- [8] बार्थन, पी. (2022). द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया (भारत में विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था) (संशोधित संस्करण). ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- [9] जाफरलोट, सी. (2021). मोदी'स इंडिया: हिंदू नेशनलिज्म एंड द राइज ऑफ एथनिक डेमोक्रेसी (मोदी का भारत: हिंदू राष्ट्रवाद और जातीय लोकतंत्र का उदय). प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
- [10] चुनाव आयोग ऑफ इंडिया. (2025). स्पेशल इंटेसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टरल रोल्स – बिहार: सुप्रीम कोर्ट निर्देश और अनुपालन रिपोर्ट (निर्वाचन सूचियों का विशेष गहन संशोधन – बिहार).
- [11] सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. (2025). एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम चुनाव आयोग ऑफ इंडिया, रिट याचिका (सिविल) नंबर 640/2025 (14.08.2025 एवं 22.08.2025 के आदेश)।
- [12] कोहली, ए. (संपा.). (2023). इंडिया'स डेमोक्रेसी: एन एनालिसिस ऑफ चेंजिंग स्टेट-सोसाइटी रिलेशंस (भारत का लोकतंत्र: बदलते राज्य-समाज संबंधों का विश्लेषण) (पुनर्मुद्रण). प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
- [13] विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार. (2024). द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, 1951 (प्रस्तावित संशोधनों सहित) (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951)।
- [14] भार्गव, आर. (2010). द प्रॉमिस ऑफ इंडिया'स सेकुलर डेमोक्रेसी (भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का वादा). ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- [15] यादव, य. (2024). "इलेक्टरल रिफॉर्म्स इन द एज ऑफ डिजिटल डेमोक्रेसी" (डिजिटल लोकतंत्र के युग में चुनावी सुधार). इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 59(12)।